



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 1993/फाल्गुन 12, 1914

No. 76] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 1993/PHALGUNA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-मूल्य परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 93

सा.का.नि. 256(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आबंधन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर. 12012/21/92-पी.ई.-I]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारियों की (आवासों का आबंधन) विनियमावली, 1993 का प्रारूप।

विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे नव मंगलूर पत्तन न्यास बोर्ड, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्रजते कि इसे केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो, उक्त अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारियों की (आवासों का आबंधन) विनियमावली, 1980 (जो 28 मार्च, 1980 को भारत के असाधारण राजपत्र स.का.नि. 150(ई) के रूप में प्रकाशित हुई) में निम्नलिखित संशोधन करना चाहता है।

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारियों की (आवासों का आबंधन) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खंड 4(1) की नीचे उपधारा (क) एवं (ख) के बाद अतिरिक्त उपधारा के रूप में निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी।

(ग) जिन कर्मचारियों ने इस बोर्ड से मकान निर्माण के लिए अधिम की सुविधाएं प्राप्त की हैं और उन्हें कार्यालय से 8 किमीटर

की दूरी पर मकान बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है, ऐसे कर्मचारियों को उक्त मकानों के निर्माण की तारीख से 3 साल तक कर्मचारी क्वार्टरों का आबंटन नहीं किया जाएगा। यदि वे पहले से ही पत्तन के क्वार्टरों में रहे हैं तो उन्हें अपने उक्त आवास के पूरा बनने के पश्चात् एक माह के अन्दर अपने पत्तन क्वार्टरों को खाली करना पड़ेगा।

3. कर्मचारी पत्तन व्याप्त कर्मचारियों (आवासों का आबंटन) विनियम 1980 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियमों के रूप में उल्लिखित किया जाएगा) के विनियम 6 में, विनियम 6 स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

6. आवासों का बंटीकरण: इन विनियमों में अन्वया उपबंधित होने के सिवाय, किसी कर्मचारी को उसकी कुल परिलब्धियों के स्वरूप जो निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं, उनकी अनुसार उचित टाइप का आवासीय मकान का आबंटन किया जाएगा:—

आवास का टाइप कर्मचारियों की श्रेणी अथवा जब उसे मकान का आबंटन किया जाता है उस वर्ष में पहले दिन की उसकी मासिक कुल उपलब्धियां

वर्ग "क" एवं "ख" के लिए वर्ग "क" एवं "ख" के लिए

टाइप "क" रु. 482 तक इसमें स्व. वि. भा. भी शामिल है।

टाइप "ख" रु. 483 से रु. 845 तक इसमें स्वा. वि. भा. भी शामिल है।

वर्ग "ग" रु. 846 से रु. 1325 तक रु. 1070 से रु. 1745 तक इसमें स्व. वि. भा. भी शामिल है।

वर्ग "घ" रु. 1326 से रु. 1425 रु. 1946 से रु. 2220 तक। इसमें स्व. वि. भा. भी शामिल है।

वर्ग "ङ" रु. 2221 से रु. 2740 तक।

वर्ग "च" रु. 2741 और आगे/अपर

वर्ग "छ" अध्यक्ष के क्वार्टरों

टिप्पणी: यदि लिखित टाइप के मकानों के आबंटन के लिए उस टाइप के पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो इन मकानों को उन कर्मचारियों को आवंटित किए जाएं जो धर्मकेन्द्रों के निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं किंतु इसमें यह शर्त होगी कि जब उक्त श्रेणी के कर्मचारी मौजूद हो जायें तो इन आवंटियों से उक्त मकानों को खाली करना लिखा जाएगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित अल्पतरफ किया जाएगा:—

7. लाइसेंस शुल्क की वसूली:—विनियम 6 के अंतर्गत आवंटित मकान/आवास के टाइप के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली के उद्देश्य के लिए कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुरूप निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे:—

(1) वे कर्मचारी जो उच्च आर. सी. वेतनमानों के अंतर्गत आते हैं, उनसे जिसमें एक एस. ए. भी शामिल है, रु. 500 तक के वेतन पर पूर्व संशोधित मूल वेतन के 7 1/2 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क वेतन पाये वाले कर्मचारियों से पूर्व संशोधित मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके अन्तर्गत क्वार्टरों के प्रत्येक टाइप के लिए अधिकतम वेतन सीमा निर्धारित करनी है।

(2) वे अधिकारी जो एस.डी. वेतनमानों के अंतर्गत आते हैं, उनसे मूल वेतन एवं अंतरिम राहत के 10 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा।

(3) इसके अतिरिक्त, ओ. एन. डी. रिपोर्ट के पैरा 5.38 के अनुसार यहाँ पत्तन प्रशासन द्वारा आवास के प्रतिमान, जिसके अधिकारी हकदार है, उससे 70 प्रतिशत कम है, वहाँ अधिकारी उस कम किए गए आवास के प्रतिमान का हकदार होगा। इसका अधिकतम सीमा के अंतर्गत लाइसेंस फीस के रूप में देगा। यह व्यवस्था विद्यमान नियमों के अनुसार की गई है।

(4) मसक लाइसेंस को मूल निशुल्क (पैरा 45(क) के अनुसार गिना जाएगा। बोर्ड के कर्मचारी से उसके स्वयं के अनुरोध पर जो उसके पद के हैसियत से अधिक है तब तक वसूल की जाएगी तब तक वह उस वर्ग के क्वार्टरों में आबंटन के लिए हकदार नहीं हो जाता है।

(5) जिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पत्तन ने अपने क्वार्टरों को आवंटित किए हैं उनसे वसुली वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकारी आदेशानुसार निम्नलिखित दरों पर लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा:—

(क) टाइप "क" पुराने क्वार्टर —रु. 35 प्र. मा

(ख) टाइप "क" नए क्वार्टर —रु. 25 प्र. मा.

(ग) टाइप "ख" पुराने क्वार्टर —रु. 60 प्र. मा.

(घ) टाइप "ख" नए क्वार्टर —रु. 35 प्र. मा.

(च) टाइप "ग" पुराने क्वार्टर —रु. 85 प्र. मा.

(छ) टाइप "ग" नए क्वार्टर —रु. 85 प्र. मा.

(ज) टाइप "घ" पुराने क्वार्टर —रु. 145 प्र. मा.

(झ) टाइप "घ" नए क्वार्टर —रु. 115 प्र. मा.

(6) वे कर्मचारी/अधिकारी जो राज्य सरकार/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड (के. ई. बी.)/स्कूल आदि से संबंधित हैं और जिन्हें पत्तन से क्वार्टर आवंटित किए गए हैं, उनसे मूल नियम 45 "क" के अंतर्गत गिने गए दर के हिसाब से मानक लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा।

(7) पत्तन के उन अवकाश प्राप्त/मृत कर्मचारियों/अधिकारियों से अनुमति प्राप्त अवधि के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा जो इन्होंने जिस अवधि के लिए पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त की है उसके लिए एन. एम. पी. टी. ई. (आवासों का आबंटन) विनियमों, 1980 के विनियम 23 के उपबंधों के अनुरूप इनसे लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी।

5. उप-विनियम (2) के बाद आने वाली तालिका के उक्त विनियमों के विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित अल्पतरफ किया जाएगा:—

बटनाए

आवासों को रखने के लिए अनुमति प्राप्त अवधि

(1) त्याग-पत्र, बरखास्तगी, सेवा से एक माह निष्कासन, सेवा की समाप्ति अथवा बिना अनुमति के अनाधिकृत गैर हाजिरी

(2) सेवा निवृत्ति अथवा अंतिम अवकाश चार माह

(3) आबंटन की मर्यादा छह माह

(iv) अवकाश (सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश) की अवधि तक किंतु काश, मना की गई छुट्टी अंतिम अवकाश, यह चार माह से अधिक नहीं विकसित अवकाश अथवा अध्ययन होना चाहिए।
अवकाश)

(v) सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश सेवा निवृत्ति से पूर्व आकाश अथवा नव मंगलोर पटन न्यास के मामले में पूरी अवधि के कर्मचारी (अवकाश) विनियम- लिए किंतु 160 दिन से अधिक मावली 1930 के नियम 28 नहीं होना चाहिए और अन्य अवकाश 29 के अंतर्गत मना की मामलों में यह अवधि चार गई छुट्टी महीने की है। सेवा निवृत्ति के मामले में अनुमति प्राप्त यानी अवधि उनमें शामिल नहीं है।

तालिका के नीचे निम्नलिखित उपबंध को जोड़ा जाएगा :—

यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी अध्ययन अवकाश को छह मास से अधिक बढ़ाता है तो छह माह के बाद उसे वह जिन आवास का हकदार है, उसमें एक टाएप नीचे का आवास विकल्प के रूप में आवंटित किया जाए अथवा यदि वह चाहे तो उसे अध्ययन अवकाश के प्रारंभ से ही यह वैकल्पिक आइटम किया जा सकता है।

6. उक्त विनियमावली के नियम 14 में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा :—

“परंतु, पूर्व आवास उक्त तारीख तक बाद में खाली नहीं, किया जाना है तो कर्मचारी को उस आवास के कब्जे के प्रयोग के लिए अनिवार्यता के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। यह भुगतान मध्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर उस तारीख से जिसमें वह बाद के आवास का कब्जा लेता है, निर्धारित किया जा सकता है।”

7. उक्त विनियमावली के विनियम 17 में उपनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

2. (क) आवास के लिए सभी आवेदनों को मध्य अधिकारी द्वारा विहित प्रथम में ही भेजा जाना है और उन्हें कलेंडर मास के 19वीं तारीख तक प्राप्त किया जाना है और इसके बाद उन्हें अगले माह की प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाएंगे। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए जिन कर्मचारियों के नामों को प्रतीक्षा सूची में इससे पूर्व माह में शामिल किए गए हैं, वे उन कर्मचारियों के नामों से पहले आएंगे जो प्रतीक्षा सूची के बाद के महीनों में शामिल किए गए हैं। किसी विशेष माह में कर्मचारियों की आपस में परस्पर वरिष्ठता को प्रतीक्षा सूची में जोड़ी जानी है तो उनका निर्धारण क्रमानुसार अथवा उनकी प्राथमिकता की तारीखों के अनुरूप किया जाएगा।

2. (ख) इनमें परिवर्तनों के लिए उपनियम 2(क) के अनुसार वरिष्ठता को निर्धारण करके प्रस्ताव भेजा जाएगा और जहां तक संभव हो सकेगा कर्मचारियों को तरजीहों को ध्यान में रखा जाएगा।

परंतु उनके निवृत्ति की आयु के तत्काल 6 माह के पूर्व की अवधि में आवास की परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्यान विनियमावली :

जहाज एवं परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) अधिभूचना के सा.का.नि. (ई) दिनांक 28 मार्च 1980।

बी. महापात्र, अध्यक्ष

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 1993

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) First Amendment Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12012/21/92-PE-I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) Regulations, 1993:—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to the approval of the Central Government, under Section 124 of the above Act, the following Regulations to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) Regulations, 1980 (Published as GSR 150(E) in the Gazette of India, Extraordinary 28th March, 1980.

1. (1) These Regulations may be called New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) (First Amendment) Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The following sub-clause shall be added as additional sub-clause after sub-clause (a) and (b) below clause 4(1).

(c) Employees who have availed the facility of H.B.A. from the Board and constructed house within a radius of 8 Kms. from the place of work when permitted to dispose of the house, shall not be eligible for allotment of staff quarters for a period of 5 years from the date of disposal. If they are already residing in the quarters at the time of disposal, they shall vacate the quarters within one month from the date of disposal of the house.

3. In Regulation 6 of New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) Regulations, 1980 (hereinafter referred to as the said Regulations) Regulation 6 shall be substituted as follows:

6. Classification of Residence:—Save as otherwise provided by these regulations, an employee shall be eligible for being allotted a residence of the type appropriate to the emoluments shown in the table below :

SCHEDULE

Category of employee or his monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made.

Type of residence	for Class III and Class IV	for Class I and Class II
Type I	Upto Rs. 482/- including SFA	—
Type-II	Rs. 483/- to Rs. 845/- including SFA	—
Type-III	Rs. 846/- to Rs. 1325/- including SFA	Rs. 1070/- to Rs. 1745/-
Type-IV	Rs. 1326/- to Rs. 1425/- including SFA	Rs. 1746/- to Rs. 2220/-
Type-V	—	Rs. 2221/- to Rs. 2740/-
Type-VI	—	Rs. 2741/- and onwards
Type-VII	—	Chairman's quarters.

Note : If sufficient number of employees who are eligible for a particular type of residences are not available, the residences, of the type may be allotted to other employees who are eligible for the next higher or lower type of residence subject to the condition that as and when eligible employees become available, the residence so allotted shall be vacated by such allottees.

4. The Regulation 7 of the said Regulation shall be modified as follows :

7. Recovery of licence fee:—For the purpose of recovery of licence fee or type of residence allotted under Regulation, 6, the following rules shall be applied as per the service conditions of the employees.

(i) In respect of the Officials borne under WRC pay scales the licence fee should be recovered @ 7-1/2 per cent of pre-revised basic pay including SFA upto Rs. 500 and beyond Rs. 500 licence fee should be recovered @10 per cent subject to the maximum pay limit fixed for each type of quarters.

(ii) In the case of Officers borne under OSD scales, the licence fee should be recovered at 10 per cent of basic pay plus adhoc relief.

(iii) Besides, as per para 5.38 of the OSD Report where the scale of accommodation provided by the Port Administration is less than 70 per cent of the scale to which the Officer is entitled, according to the rules currently in force, the recovery of licence fee should be limited to the maximum

licence fee that might be payable by an Officer eligible for that reduced scale of accommodation.

(iv) Standard licence fee calculated under FR 45(A) shall be recovered for a residence allotted to an employee of the Board at his own request which exceeds to the status of the post held by him till he becomes eligible for allotment of that type of quarters.

(v) In the case of Central Government employees who have been allotted with port quarters, the following flat rate of licence fee should be recovered as per the orders of the Government based on the 4th Pay Commission recommendation :

(a) Type I Old quarters	—Rs. 35 p.m.
(b) Type I New quarters	—Rs. 25 p.m.
(c) Type II Old quarters	—Rs. 60 p.m.
(d) Type II New quarters	—Rs. 35 p.m.
(e) Type III Old quarters	—Rs. 85 p.m.
(f) Type III New quarters	—Rs. 85 p.m.
(g) Type IV Old quarters	—Rs. 145 p.m.
(h) Type IV New quarters	—Rs. 115 p.m.

(vi) In the case of employees/officers of the State Govt./K.E.B./School etc., who have been allotted with I Port quarters the standard licence fee shall be recovered as calculated under FR 45A.

(vii) For retired/expired officials/officers of the Port, normal licence fee should be recovered for the permissible period and beyond the permissible period the licence fee should be recovered as per the provisions of Regulation 23 of New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) Regulations, 1980.

5. In Regulation, 13 of the said Regulation, the table coming after sub-regulation (2) shall be modified as follows :

Events	Permissible period for retention of residences
(i) Resignation, dismissal, removal from service, termination of service of unauthorised absence without permission.	One month
(ii) Retirement or terminal leave.	4 months
(iii) Death of the allottee	6 months
(vii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave).	For the period of leave but not exceeding 4 months.
(viii) Leave preparatory to the retirement or refused leave under Regulation 28 or 29 of the new Mangalore Port Employees (Leave) Regulations, 1980	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 180 days in the case of leave preparatory to retirement and 4 months in other cases inclusive of the period permissible in the case of retirement.

The following proviso shall be inserted below the Table.

If the study leave is extended beyond 6 month, he may be allotted alternative accommodation, one type below his entitlement on the expiry of 6 months or from the date of commencement of the study leave, if he so desires.

6 In regulation 14 of the said Regulation the following proviso shall be added.

"Provided that the former residence is not vacated by the subsequent date as aforesaid, the employee will be liable to pay damages for use and occupation of the residence as may be determined by the competent authority from time to time from the date he takes possession of the latter residence".

7. In Regulation 17 of the said regulation the sub-regulation 2 shall be substituted as follows :—

2(a) All applications for residence made in the form prescribed by the competent authority and received upto 19th date of calendar month shall be included in the waiting list in the succeeding month. For purpose of these Rules, the

employees whose names are included in the waiting list in the earlier month shall be senior en-bloc to those whose names are included in the list in subsequent months. The inter-seniority of the employees included in the list in any particular month shall be determined in the order or their priority dates.

2(b) The changes shall be offered in the order of seniority determined in accordance with sub-rule 2(a) and having regard to the employees' preferences as far as possible.

Provided no change of residence shall be allowed during a period of 6 months immediately preceding their date of superannuation.

Principal Regulations :

Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)
Notification at GSR 150(E) dated 28th March, 1990.

Sd/-
B. MAHAPATRA, Chairman